एनआईसी तेलंगाना: हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण के लिए शून्य परमिट प्रणाली।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तेलंगाना राज्य (एनआईसी टीजी), खान और भूविज्ञान विभाग के सहयोग से, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) इंजीनियरिंग डिवीजन के लिए शून्य परमिट प्रणाली को डिजाइन और लागू किया। इस प्रणाली को खान और भूविज्ञान विभाग के लिए प्रतिष्ठित परियोजना के एक अभिन्न घटक के रूप में विकसित किया जा रहा है।

एचएमडीए परियोजनाओं में लगे सभी ठेकेदारों को सरकार द्वारा अधिदेशित कार्य के लिए शून्य परमिट प्रणाली का उपयोग करने के लिए खनिज डीलर लाइसेंसधारी (एमडीएल) धारकों के रूप में पंजीकरण करना आवश्यक है। एचएमडीए से कार्य पुरस्कार प्राप्त करने पर, ठेकेदार एचएमडीए इंजीनियरिंग डिवीजन के मुख्य अभियंता (सीई) या कार्यकारी अभियंता (ईई) पर ऑनलाइन आवेदन करता है, जो आवश्यक खनिजों की एक सूची और मात्रा प्रदान करता है। सीई/ईई कार्य और निर्दिष्ट मात्रा की समीक्षा, अनुमोदन और प्रमाणीकरण करता है। इस अनुमोदन के बाद, ठेकेदार वैध पारगमन पास का उपयोग करके सामग्री जुटाना शुरू कर सकता है।

इससे पहले, वैध पारगमन पास की कमी वाले खनिज परिवहन के कारण अक्सर सतर्कता बिंदुओं पर अनावश्यक जांच होती थी। इस नई प्रणाली के साथ, वाहन चलाना प्रामाणिक रूप से सत्यापित है। इसके अलावा, यह प्रणाली प्रत्येक विभागीय परियोजना के लिए खनिज खपत को समेकित और ट्रैक करने में खान और भूविज्ञान विभाग और एचएमडीए दोनों की सहायता करती है।

इस प्रणाली का विस्तार खनिज परिवहन से संबंधित किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग विभाग तक किया जा सकता है।

एचएमडीए के इंजीनियरिंग विभाग के लिए शून्य परमिट प्रणाली पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

****